12.57 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Distribution of Surplus Land to the poor for effective implementation of the 20 Point Programme

श्रीमती ऊषा वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर तथा ग्रामीणों में जो भी छोटी बड़ी योजनायें लागू की गई हैं, चाहे वह बैंक के द्वारा हो या ब्लाक के द्वारा, उनसे जो लाभ गरीबों को मिलना चाहिए वह उनको नहीं मिल रहा है। जैसे डी०आर०आई० को लीजिए। इसको लेने के लिए जो व्यक्ति जाता है उसको एक-एक वर्ष तक दौड़ाते रहते हैं जिससे गरीब व्यक्तियों को बहुत ही परेशानी उठानी पड़ती है।

यही नहीं जिन गरीब लोगों को भूमि आवंटित की गई है उनको भी विशेष परेशानी उठानी पड़ती है। मेरे प्रान्त में बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन लोगों को पट्टे मिले हैं उनको अभी तक यह भी पता नहीं है कि हमारी जमीन कहां पर है। वे अपने गांवों से डिस्ट्रिक्ट तक हजारों बार चक्कर लगा चुके हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मजदूर व्यक्ति अपने बच्चों का पालन-पोषण करने में भी असमर्थ हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो भी जमीनें सीलिंग की ग्राम समाज की हैं उनको वह अपने कब्जे में लेकर उन गरीबों को बांटें जिससे वे अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकें।

गरीब कृषक को जमीन का समुचित उपयोग करने हेतु बीज, खाद एवं अन्य कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिए सरकार पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान करें, उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाए ताकि वे लोग सुख शांति की जिन्दगी जी सकें और उनके बच्चों का जीवन सुखमय हो सके।

मेरी केन्द्र सरकार से प्रार्थना है कि वह इस ओर विशेष ध्यान देकर तत्काल इस कार्य को क्रियान्वित करे ताकि बीस सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्ण हो सके।

13 hrs.

(ii) Measures for stopping felling of green trees in Purnea and other parts of Bihar

श्रीमती माधुरी सिंह (पूर्णिया) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में पर्यावरण में सुधार करने के लिए सारे विश्व में ध्यान दिया जा रहा है। आज हम भली प्रकार जानते हैं कि प्रकृति और राष्ट्रीय समृद्धि में परस्पर गहरा संबंध है। पेड़-पौधों का व्यक्ति के स्वास्थ्य, आर्थिक उन्नति और वातावरण से आज संबंध निश्चित रूप से सिद्ध हो गया है। लेकिन यह खेद का विषय है कि बिहार के पूर्णिया ज़िले में हरे-पेड़ों की विवेकहीन ढंग से कटाई हो रही है। इससे सम्पूर्ण क्षेत्र प्रभावित है। भविष्य में यह क्षेत्र रेगिस्तान में बदल कर सूखे की आशंका से घिर जाएगा और स्थानीय आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी काफी कठिनाइयां पैदा कर देगा। जो लोग अधिकांश वन-सम्पदा पर निर्भर रहते हैं, आज पेड़ों की अवैध कटाई से इन निर्धन लोगों का शोषण हो रहा है। पूर्णिया किसी समय पूर्णिया आम की अच्छी किस्म के लिए विख्यात था, लेकिन उनके लिए वरदान स्वरूप आम के पेड़ धीरे-धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। इन पेड़ों की अवैध कटाई में स्थानीय असामाजिक तत्वों का हाथ है और वे लोग इसमें पैसा कमा रहे हैं। पूर्णिया ज़िले में आम के पेड़ों की एक तिहाई संख्या अवैध कटाई का शिकार बन चुकी है और वनों की कटाई अब भी निरन्तर जारी है। असली अपराधियों को आज तक नहीं पकड़ा गया है, जबकि बिना सोचे समझे यह आरोप आदिवासियों पर थोप दिया जाता है। पेड़ों को काटने से गरीब वर्ग के लोगों का जीवन-निर्वाह होता था, अब उन्हें पकड़कर पुलिस ले जाती है और यह लकड़िया ठेकेदारों द्वारा चार गुना कीमत में बिकती हैं।

मेरा निवेदन है कि पेड़ों की अवैध कटाई

तुरन्त बन्द होनी चाहिए। पेड़ों के विनाश से इस क्षेत्र में वन्य पशु-पक्षी, प्राकृतिक सुषमा, जलवायु आदि भी प्रभावित हो रहे हैं। सरकार द्वारा इस ओर ध्यान देकर पुर्णिया जिले और बिहार में पर्यावरण समुन्नत करने के लिए तुरन्त कदम उठाने चाहिए।

(iii) Shortage of Application Forms with the Union Public Service Commission

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : उपाध्यक्ष महोदय, संघ लोक सेवा आयोग के मुख्यालय में आवेदन-पत्रों (एप्लीकेशन फार्मस्) की इस कदर कमी हो गई है कि पिछले दो सप्ताह से आयोग ने दिल्ली के बाहर फार्म भेजना बन्द कर दिया है, जबकि विभिन्न पदों के लिए छः हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र मंगवाए हुए हैं। यह स्थिति अभी कुछ दिन और बने रहने की आशंका है। केन्द्र व राज्यों के हज़ारों सरकारी पदों के लिए नियुक्तियां करने वाले इस आयोग के पास आवेदन-पत्रों की कमी का मामला इसलिए और भी संगीन हो गया है कि आयोग ने कुछ ही समय पूर्व लाखों रुपये की लागत से अपना आफसेट छापाखाना लगाया है। दिलचस्पी की बात यह भी है कि पिछले दो ढ़ाई महीनों से आवेदन पत्रों की कमी होने के बावजूद अपने छापेखाने का इस्तेमाल आयोग ने तब तक नहीं किया जब तक आवेदन पत्रों का स्टाक एकदम खत्म नहीं हो गया। किसी तरह बाजार से आफसेट प्लेट बनवाकर तथा अपने छापेखाने में ओवरटाइम काम करवा कर आयोग ने चार-पाँच हजार फार्म छपवा लिए हैं। अधिकारियों ने दिल्ली से बाहर डाक से फार्म भेजने की मनाही कर दी है और यूपी एससी भवन के काउन्टर पर एक व्यक्ति को एक ही फार्म देने का आदेश लागू कर दिया है। इस प्रकार दिल्ली में रह रहे व्यक्ति को तो फार्म उपलब्ध है, किन्तु दिल्ली से बाहर के किसी भी व्यक्ति को फार्म नहीं भेजे जा रहे। इस प्रकार दिल्ली से बाहर के कितने प्रत्याशी कितनी परीक्षाओं एवं साक्षात्कारों के अवसर खो बैठेंगे, इसका ठीक-ठाक अन्दाजा लगाना कठिन है। लेकिन आयोग के सूत्रों के अनुमान के मुताबिक ऐसे प्रत्याशियों की संख्या हजारों में होगी।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले की गंभीरता को समझते हुए संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारियों को निर्देश देकर शीघ्र से शीघ्र आवेदन पत्रों में इस अभाव को समाप्त करायें।

(iv) Need for arresting the declining trend in export of canned fruit products to USSR

SHRI S.T.K. JAKKAYAN (Periyakulam) : The U.S.S.R. has been the traditional importer of Indian canned products like juices, jam, pulp, etc. from the annual average of 8,000 to 10,000 tonnes, this reached 47,000 tonnes in 1982 and the value was about Rs. 38 crores. But unfortunately in 1982 a disturbing trend started in the sense that the USSR started making claims against Indian suppliers on an average of 10% to 12% on the grounds of defective packaging, denting of cans, etc., though the Indian suppliers did not receive any such claims from other countries to whom they have exported processed fruit products.

In 1983, the USSR buyers have slashed their purchases to 28,000 tonnes valued at approximately Rs. 22 crores. Even here, they have been shifting their grounds in respect of shipments. First, they wanted the shipments to be effected only after July, which has been postponed to September, 1983. Suddenly, now it is reported that they want indefinite postponement. Any further postponement of shipment means decimation of this industry as a whole because the products are perishable. Secondly, the subsidiary industries engaged in can-making and such other inputs would also be closed.

It is suggested that the Government should try to arrest this destabilising trend by immediately initiating mutual discussions for arriving at an agreed solution, so that the situation within the country is not further aggravated.